

भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों और 7.8 प्रतिशत की जीडीपी

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत आंकड़ों और 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर सीधा हमला बोला है। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कमजोर देशों की सूची में शामिल करने वाले लोग जीडीपी पर संदेह जटा रहे हैं। अपनी सरकार के कार्यकाल में जीडीपी की मजबूत वृद्धि सहित देश में हुए सकारात्मक घटनाक्रमों पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जन्मजात निराशावादी और दोषारोपण करने वाले बताते हुए उन पर जमकर निशाना साधा। कहा कि देश की प्रगति से चिढ़ने वाले लोग झूठ का अभियान चला रहे हैं, लेकिन अंततः सत्य की शक्ति ही विजयी होगी।

पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में

इस मानसिकता को बढ़ावा देने वालों का असली जनता चेहरा अच्छी तरह पहचान चुकी है।

आए सकारात्मक बदलावों और 7.8 प्रतिशत की प्रभावशाली तिमाही जीडीपी वृद्धि दर पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कभी भारत को कमजोर पांच देशों की श्रेणी में रखते थे, वे आज देश की आर्थिक प्रगति और विकास के आंकड़ों को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तुलना परिवार के नाराज फूफा और चिरस्थायी चाचा से करते हुए कहा कि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हर अच्छी बात में कमी निकालने की आदत है और जिनके लिए गिलास कभी आधा भरा नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जीडीपी के आंकड़ों

पर संदेह जताने वाले ठीक वही लोग हैं जिन्होंने जन धन योजना से लेकर मेक-इन-इंडिया तक सरकार की हर नीतिगत पहल का विरोध किया था।

पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि यूरोप और पश्चिम एशिया में जारी युद्धों और वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों के बावजूद भारत ने यह प्रभावशाली विकास दर हासिल की है। आलोचकों के झूठ के अभियान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि झूठ की गूंज के खिलाफ अंततः सत्य की हुंकार ही प्रबल होगी और सच्चाई की जीत होगी। अपने भाषण में दिमागी नक्सल वाली टिप्पणी पर जारी विवाद का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने होम्योपैथिक गोली दी थी और सारे दिमागी नक्सल रंगते हुए बाहर आ गए। देश की जनता इस मानसिकता को बढ़ावा देने वालों का असली चेहरा अच्छी तरह पहचान चुकी है।

प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र का समर्थन नहीं करता

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के समान क्षेत्रफल वाले ग्लोबल मैप के समर्थन में मतदान तो किया है, लेकिन इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव किसी विशेष मानचित्र का समर्थन नहीं करता है और भारत के संप्रभु क्षेत्र को उसके आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह प्रस्ताव किसी विशेष विश्व मानचित्र को न तो अपनाता है और न ही उसे प्रमाणित करता है और न ही इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, विवादित क्षेत्रों या स्थानों के नामों सहित राजनीतिक मानचित्रकला पर कोई चर्चा की गई है।

भारत ने अपने मत की व्याख्या का इस्तेमाल जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पर अपनी स्थिति को दोहराने के लिए किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों सहित भारत के संप्रभु क्षेत्र को भारत के

केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बने

भारत के किसी भी जनपद, तहसील या थाना क्षेत्र में केशरी दर्पण समाचार पत्र के पत्रकार बनने के लिए संपर्क करें। आप केशरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट से भी के माध्यम से भी पत्रकार बन सकते हैं। समाचार पत्र की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करें लॉगिन करें आप स्वयं केसरी दर्पण समाचार पत्र की वेबसाइट पर समाचार फोटो आदि भी अपलोड कर सकते हैं। सोनीपत जनपद में श्रीमती अंजू देवी पति श्री कृष्ण पाल, सोनीपत मो. 9416957607

निवेदक-सुभाष चंद, संपादक, केशरी दर्पण (हिंदी साप्ताहिक) 9837749557

www.kesharidarpan.com

आधिकारिक मानचित्र के अनुसार ही दर्शाया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का गलत या भ्रामक चित्रण अस्वीकार्य है। भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमारा रुख स्पष्ट, सुसंगत और अपरिवर्तनीय है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 सितंबर को प्रस्ताव स्वीकार किया, शीर्षक था— मानचित्र को सही करें- वैश्विक मानचित्र

संबंधी प्रतिनिधित्व को पुनर्संतुलित करना और विश्व के क्षेत्रों के न्यायसंगत प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना। प्रस्ताव 164 मतों के भारी समर्थन से पारित हुआ, इसके विरोध में केवल एक मत पड़ा। इस प्रस्ताव के तहत ऐसे समान क्षेत्रफल वाले मानचित्रों के उपयोग को प्रोत्साहित किया, जो महाद्वीपों के वास्तविक और तुलनात्मक आकार को सही रूप में दर्शाते हैं।

केंद्र की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

विशाल कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार की 3,100 से अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं और 360 से ज्यादा सार्वजनिक सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। लेकिन जो अधिकारी देश की सबसे गरीब नागरिकों से हर योजना के लिए आधार मांगती है, वही अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड को आधार से लिंक कराने का कड़ा विरोध कर रही है।

केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, मौजूदा और पूर्व सांसद, सुप्रीम कोर्ट और

हाई कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जज, और दिल्ली में मान्यता प्राप्त पत्रकार शामिल हैं। स्पष्ट किया था कि आधार से योजनाओं को लिंक करने से लक्षित, पारदर्शी और पारसमुक्त वितरण सुनिश्चित होता है, जिससे डुप्लिकेट और अयोग्य लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाती है।

इसके बावजूद, इस नियम को लागू करने वाले अधिकारी स्वयं इसका पालन नहीं कर रहे हैं। मृत पेंशनभोगियों या अपात्र हो चुके आश्रितों को हटाने के लिए कोई वार्षिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया संचालित नहीं की जाती। पूर्व सैनिकों की

स्वास्थ्य योजना और रेलवे की स्वास्थ्य सेवा में आधार लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार ने जून 2015 से आधार लिंकिंग अनिवार्य करने हेतु कई कार्यालय ज्ञापन जारी किए, लेकिन कर्मचारियों के तीखे विरोध के कारण हर बार इसे वापस लेना पड़ा।

जुलाई 2024 में भी सरकार को छत्र ास लाभार्थी आईडी को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी से जोड़ने के आदेश को अगले आदेश तक स्थगित करने पर मजबूर होना पड़ा।

सरकार ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में आठ चीफ जस्टिस नियुक्त किए

अनुष्का कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। शनिवार को केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट में आठ चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं। यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के कुछ दिनों बाद हुई हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लुरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वहीं, मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे।

जस्टिस वल्लुरी कामेश्वर राव दिल्ली हाई कोर्ट - पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रविंद्र वी घुगे बॉम्बे हाई कोर्ट -

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी इलाहाबाद हाई कोर्ट- बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट - पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस कृष्णा राम मोहापात्रा (ओडिशा हाई कोर्ट - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस अलपेश यशवंत कोगजे (गुजरात हाई कोर्ट- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी (राजस्थान हाई कोर्ट - जम्मू- कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुई हैं। की हुई है। अचानक एक साथ इतनी नियुक्ति क्या सन्देश देती है।

राहत किट का वितरण 48 घंटे के भीतर प्रभावित लोगों के बीच सुनिश्चित किया जाए

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। जनपद चित्रकूट का भ्रमण कर लौटते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए और फसल तथा मकान की क्षति का तत्काल सर्वे कराकर पात्र लोगों को नियमानुसार सहायता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के कैचमेंट एरिया में हुए अतिक्रमण का चिन्हांकन कर उसे हटाने की कार्रवाई कराने, नदी पर बने फुट ओवर ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट कराने तथा मंदाकिनी में सीवर और नालों का पानी किसी भी दशा में न जाने देने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। चित्रकूट धाम के व्यापारियों और मठ मंदिरों को हुए नुकसान का आकलन कर सहायता उपलब्ध कराने भविष्य में ऐसी स्थिति से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने को कहा।

बाढ़ से प्रभावित किसानों की फसल क्षति का सर्वे शीघ्र पूरा कराया जाए और पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए भी प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

चित्रकूट धाम के व्यापारियों को हुए नुकसान का आकलन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित व्यापारियों को सहायता और मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। मठ-

मंदिरों को हुई क्षति का भी सर्वे कराया जाए और उनकी मरम्मत का कार्य शीघ्र शुरू कराया जाए। इन धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण में शासन आवश्यक सहयोग करेगा।

राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शेष राहत किट का वितरण 48 घंटे के भीतर प्रभावित लोगों के बीच सुनिश्चित किया जाए। राहत सामग्री पहुंचाने में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रशासन प्रभावित परिवारों के बीच लगातार मौजूद रहकर उनकी जरूरत के अनुसार सहायता उपलब्ध कराए।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उपलब्ध रहें और प्रभावित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता समय पर मिले। उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी जरूरी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखें और किसी भी बीमारी के लक्षण सामने आने पर तत्काल उपचार और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने मंदाकिनी नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण के संबंध में शासन के अधिकारियों को जनपदीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद करने के निर्देश दिए।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कमान शोध और अकादमिक प्रशासन के अनुभवी प्रो. कृष्णपाल सिंह को

नितिन कुमार सिंह, बागपत। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कमान शोध और अकादमिक प्रशासन के अनुभवी प्रो. कृष्णपाल सिंह को सौंपी है। प्रो. केपी सिंह मूल रूप से बागपत क्षेत्र के बड़ौत के रहने वाले हैं। उन्हें कुलपति नियुक्त किए जाने से गांव में खुशी है। वहीं इस उपलब्धि से जिले का भी मान बढ़ा है। कंडेरा के शिक्षक सुखबीर सिंह के घर जन्मे प्रो. कृष्णपाल सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई।

हाईस्कूल बामनौली इंटर कालेज से किया। इंटर व बीएससी अलीगढ़ से की। इसके बाद एमएससी, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। कृष्णपाल ने आरके कालेज शामली से अध्यापन कार्य शुरू किया था। फिर मुजफ्फरनगर के डीएवी कालेज में सेवा दी। इसके बाद पश्चिम की नामचीन संस्था जेवी कालेज बड़ौत में वर्ष 1998 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य शुरू किया। इसके बाद विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति रहे।

अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किए जाने से गांव में खुशी का माहौल है। उन्होंने लगातार जिले का मान बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में बागपत आकर

स्थानीय सांसद डा. राजकुमार सांगवान के चुनाव में भी कार्य किया था। प्रो. केपी सिंह तीन भाई हैं। बड़े भाई वीरपाल सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं, जो बड़ौत में रहते हैं। तीसरे भाई शामली में निवासरत हैं। प्रो. केपी सिंह खुद बरेली में रहते हैं। पिछली वर्ष होली पर वह गांव आए थे। मूल रूप से बड़े किसान हैं। तीनों भाइयों के पास 150 बीघा खेती की जमीन है।

प्रदेश की राज्यपाल द्वारा शनिवार को जारी आदेश में प्रो. केपी सिंह को अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त मिली है। छपरौली विधायक डा. अजय कुमार, पूर्व विधायक सहेंद्र सिंह, रालोद के राष्ट्रीय सचिव डा. कुलदीप उज्ज्वल, रमाला सहकारी चीनी मिल के उपसभापति जयदेव सिंह, डा. यशवीर सिंह, डा. दुष्यंत कुमार ने हर्ष व्यक्त किया। उधर, उनके भाई इंजीनियर वीरपाल सिंह ने भी खुशी जताई है।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के नेतृत्व को लेकर चल रहा इंतजार शनिवार को समाप्त हो गया। राजभवन ने विश्वविद्यालय की कमान शोध और अकादमिक प्रशासन के अनुभवी प्रो. कृष्णपाल सिंह को सौंप दी। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए

कुलपति नियुक्त किया है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के कुलपति रह चुके प्रो. सिंह की पहचान बायोफिजिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ के रूप में है।

प्रो. केपी सिंह मूल रूप से बागपत क्षेत्र के बड़ौत के रहने वाले हैं। उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले प्रो. सिंह वर्ष 2005 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर से जुड़े। उन्होंने वहां बायोफिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला और बाद में प्रोफेसर बने। उनका प्रमुख अकादमिक कार्य विश्वविद्यालय के कालेज आफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज की बायोफिजिक्स यूनिट में रहा।

प्रो. सिंह ने पंतनगर में बायो-नैनोटेक्नोलॉजी और नैनो-बायोसेंसर से जुड़े शोध को नई दिशा दी। उनके शोध का दायरा कृषि क्षेत्र तक भी पहुंचा। नैनो-सिलिका में यूरिया को समाहित कर नैनो उर्वरक तैयार करने और उसके फसलों पर प्रभाव का अध्ययन उनके प्रमुख शोध कार्यों में शामिल रहा। इसके अलावा ग्राफीन आक्साइड, नैनोपोरस मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर के माध्यम से जैव-अणुओं की पहचान, कैंसर उपचार में लक्षित दवा वितरण व बायोमेडिकल नैनो टेक्नोलॉजी पर भी उन्होंने शोध किया।

योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प करने जा रही

प्रमोद कश्यप/एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं और मेडिकल इमरजेंसी में होने वाली मौतों को रोकने के लिए योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा कायाकल्प करने जा रही है। यूपीटीईएन के जरिए प्रदेश की बिखरी हुई ट्रामा, बर्न, कार्डियक और स्ट्रोक जैसी इमरजेंसी सेवाओं को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा, ताकि गोल्डन ऑवर शुरुआती 60 मिनट में हर मरीज को तत्काल जीवनरक्षक उपचार मिल सके।

मरीजों को नजदीकी और सक्षम चिकित्सा केंद्र तक तेजी से पहुंचाने के लिए 173 एकीकृत ट्रामा एवं इमरजेंसी मेडिसिन यूनिट विकसित की जाएंगी। इनमें 11 लेवल-1 एपेक्स हब, 36 लेवल-2 रीजनल सेंटर और 126 लेवल-3 जिला स्तरीय इकाइयां शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित घोष के अनुसार, नेटवर्क का मुख्य लक्ष्य हर साल 10 से 12 हजार अनमोल जानें बचाना और स्थायी विकलांगता के मामलों में भारी कमी लाना है।

नई व्यवस्था में मरीज के अस्पताल पहुंचने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि सूचना मिलते ही इलाज शुरू हो जाएगा। 1,200 एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को नेटवर्क से जोड़कर चलते-

फिरते आपात उपचार केंद्र में बदला जाएगा।

प्रदेश के 18 मंडलीय कमांड सेंटर्स के जरिए एंबुलेंस, अस्पतालों के बेड और विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच रियल-टाइम कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित होगा। आपातकालीन प्रतिक्रिया समय को 30 से 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए डिजिटल अलर्ट सिस्टम और एआई आधारित ट्रैजेज तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम 'राइट मरीज, राइट डिपार्टमेंट और राइट टाइम' के सिद्धांत पर काम करेगा, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले ही यह तय हो जाएगा कि मरीज को सीधे किस विशेषज्ञ के पास भेजना है।

किसी भी आपात स्थिति में आम आदमी के उपचार में आर्थिक कारणों से देरी न हो, इसके लिए शुरुआती 48 घंटे का इमरजेंसी इलाज पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इसके अलावा तीन स्तरों पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें पुलिस, फायर सर्विस और हाईवे पेट्रोल के साथ-साथ आम नागरिकों को भी शुरुआती मदद की ट्रेनिंग दी जाएगी। विशेषज्ञों को जोड़े रखने के लिए एम्स की तर्ज पर अलग कैडर और वेतनमान की व्यवस्था भी लागू की जाएगी।

कोशिश करो

तैयार रहो

सेवा करो

श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन

पंजीकरण संख्या- S/703/2014-दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 2014, संपूर्ण भारतवर्ष
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्काउट्स-गाइड्स जर्मनी से भी संबंध
प्रधान कार्यालय: निर्भय एनक्लेव, खेकड़ा (बागपत) उ.प्र. पिन-250101
Email:- subhashchand4@gmail.com, Mob- 09837749557- 7906984078



संपूर्ण भारतवर्ष में श्रीराम बाजपेयी स्काउट-गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, स्काउट-गाइड प्रशिक्षण कैंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, सिलाई सेंटर हेतु संपर्क करें।
स्काउट गाइड संस्थाओं NCC, NSS से जुड़े भाई-बहनो जुड़ने को प्राथमिकता।

(सुभाष चंद कश्यप, राष्ट्रीय महासचिव, श्रीराम बाजपेयी स्काउट गाइड एसोसिएशन)

इकोनामिक कारिडोर पर वाहनों की स्पीड 200 घंटा के दाम अब भी तेज भाग रहे

नितिन कुमार सिंह, बागपत। इकोनामिक कारिडोर दिल्ली-देहरादून पर वाहनों की रफ्तार ने रिकार्ड तोड़ दिया है। इस पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित है, इसके बावजूद यहां पर एक थार गाड़ी 200 की स्पीड पर फरफटे भरती मिली। इसी तरह एक फार्च्यूनर गाड़ी 180 की स्पीड पर दौड़ती मिली। पिछले करीब साढ़े चार माह में 1,083 वाहन ओवर स्पीड पर मिले हैं, जिनके चालान किए गए। चंद सेकेंड की जल्दबाजी में वाहन चालक अपनी और दूसरे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जरूरी है कि सफर करते समय यातायात नियमों का पालन करें।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 14 अप्रैल को इकोनामिक कारिडोर का उद्घाटन किया था। कार की निर्धारित स्पीड 100 किमी. प्रति घंटा और ट्रक-बस की स्पीड 80 किमी प्रति घंटा है। इसकी अनदेखी करते हुए चालक हवा की तरह वाहनों को

दौड़ा रहे हैं। एआरटीओ विपिन कुमार ने इंटरसेप्टर से कारिडोर पर पहुंचकर इंटरसेप्टर से चेकिंग की तो वाहनों स्पीड ने चौंका दिया। बड़ी संख्या में वाहन ओवरस्पीड दौड़ते दिखाई दिए। थार गाड़ी दिल्ली और फार्च्यूनर गाड़ी देहरादून के नाम पंजीकृत है। 130 से 160 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर दौड़ने वाले वाहनों की संख्या 500 से अधिक पहुंच गई है। सड़क दुर्घटना की मुख्य वजह भी ओवरस्पीड माना जा रहा है। कारिडोर पर कई घटना तो खड़े ट्रक व अन्य वाहनों से दूसरे वाहनों के टकराने से हुई है। ऐसे में कई लोगों की जान जा चुकी है।

इकोनामिक कारिडोर पर दुपहिया, श्री व्हीलर और ट्रैक्टर-ट्राली का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद प्रतिबंधित वाहन दौड़ते हैं। कार व दोपहिया वाहन कारिडोर पर दौड़ते हुए मोबाइल से वीडियो बनाकर युवा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करते रहते हैं। कई वीडियो पर

संज्ञान लेते हुए पुलिस वाहनों के चालान कर चुकी है। इकोनामिक कारिडोर पर दौड़ते हुए ट्रक का टायर फट गया था। इससे अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया था। उसमें सवार 24 वर्षीय समीर और 19 वर्षीय सुहैब निवासीगण बागपत घायल हो गए थे।

ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर वाहन की अधिकतम 120 किमी प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित है। दिल्ली-देहरादून इकोनामिक कारिडोर पर वाहनों की अधिकतम स्पीड 100 किमी प्रति घंटा निर्धारित है। दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे और मेरठ-बागपत-सोनीपत हाईवे पर वाहन की अधिकतम 80 किमी. प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित है। मेरठ-बड़ौत हाईवे पर अधिकतम 60 किमी. प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित है। ब्लैक स्पार्ट पर अधिकतम 30 किमी. प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित है। आबादी क्षेत्र में अधिकतम 30 किमी. प्रति घंटा की स्पीड निर्धारित है।

अंजू देवी, सोनीपत। प्याज के दाम अब भी तेज भाग रहे हैं। महज दस दिन पहले 40 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज खुदरा बाजार में उछलकर 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा में चीनी 70 रुपये से 62 तक लौट आई है। थोक मंडी में प्याज 45 से 55 रुपये प्रति किलो की बोली पर छूटा। अचानक आई इस तेजी से मध्यम और गरीब वर्ग का मासिक बजट पूरी तरह चरमरा गया है। वहीं फलों, हरी सब्जियों, दालों व रसोई से जुड़ी अन्य चीजों पर महंगाई की मार है।

सब्जियों के दामों में उछाल का मुख्य कारण पिछले दिनों हुई भारी वर्षा है। खेतों में पानी भर जाने से स्थानीय फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बाहरी राज्यों से आने वाली मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। नतीजतन थोक मंडियों में सब्जियों की दैनिक

आवक आधी रह गई है।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर बाजारों में रौनक तो है। महंगाई का साया साफ देखा जा रहा है। व्रत और भोग के लिए सूखे मेवों तथा फलों की मांग बढ़ने से भाव चढ़े हुए हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू 1000 रुपये, बादाम 900 से 1080 रुपये और पिस्ता 1400 से 1700 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि, फलों में सेब 150 रुपये व आम 300 से 350 रुपये के उच्च स्तर पर हैं, जबकि केला व अनार की कीमतों में मामूली नरमी देखी गई है।

लगातार हो रही वर्षा के कारण खेतों में जलभराव है, जिससे तोड़ी गई हरी सब्जियां मंडियों तक पहुंचने से पहले ही सड़ रही हैं। प्याज और लहसुन की खेप कम आ रही है। थोक में ही माल महंगा मिल रहा है, ऊपर से जन्माष्टमी के चलते व्रत वाली सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई है।

भाजपा ने गरीबों को हमेशा धोखा दिया, गरीबों के आरक्षण में दबंगों को शामिल कर गरीबों का पिछले 26 वर्षों से मार दिया, आओ बागपत लोकसभा को भाजपा मुक्त करे

बागपत लोकसभा की जनता जनार्दन आशीर्वाद दे तो एक बार फिर 2029 में निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा



निवेदक-

सुभाष चंद कश्यप

पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा
2014 निर्दलीय, 7906984078

पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर
11 जनपद बागपत-2015

राष्ट्रीय महासचिव श्रीराम बाजपेई स्काउट
गाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया

पता- कस्बा खेकड़ा जनपद बागपत उत्तर
प्रदेश -250101

सम्पादकीय.....

भारत को पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकी संगठनों की ओर से सतर्क रहने की जरूरत

पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच सुरक्षा समझौता होने के करीब एक महीने बाद, पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि इस तरह का समझौता पाकिस्तान में अति आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। इसका नतीजा जल्द ही उसकी हरकतों में दिखाई दे सकता है। इसलिए भारत को पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकी संगठनों की ओर से सतर्क रहने की जरूरत है। भारत की सुरक्षा के लिए खतरे और चुनौती विषय पर आयोजित व्याख्यान में तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुख चौहान ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान आने वाले समय में बड़ा खतरा बनने वाला है।

सीडीएस चौहान ने कहा कि आपरेशन सिंदूर, सिंधु जल समझौते के निलंबन और कुछ अन्य व्यावहारिक कदम उठाए जाने से उम्मीद बनी थी कि पाकिस्तान के आचरण में बदलाव आएगा। हाल के समझौते से पाकिस्तान में अति आत्मविश्वास पैदा हुआ है। इसके दुष्परिणाम निकट भविष्य में सामने आ सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत होगी। विदित हो कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये का सुरक्षा समझौता गत सात अगस्त को हुआ था। इस समझौते के अनुसार किसी एक देश पर हुआ हमला सभी तीन देशों पर हुआ हमला माना जाएगा और तीनों ही देश उसका जवाब देंगे।

पूर्व सीडीएस चौहान ने कहा कि चीन हमारे लंबे समय से चुनौती बना हुआ है। उसके साथ भारत का सीमा विवाद काफी पुराना है। लेकिन दोनों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझौता लागू है। इसलिए केवल सीमा के मसले पर चीन के साथ संबंध खराब नहीं किए जा सकते हैं। सावधानी जरूरी है।

जनगणना-2027 के दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के 31 जिलों से नामित मास्टर ट्रेनरों को चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण 16 से 19 सितंबर तक दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान लखनऊ में होगा। प्रशिक्षण से एक दिन पहले 15 सितंबर को ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें सभी मास्टर ट्रेनरों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव और वाराणसी के नामित मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण में शामिल होंगे।

महाभारत कालीन नगरी में श्री महानंद संस्कृत विद्यालय लाक्षागृह प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा का एक जीवंत प्रतीक

नितिन कुमार सिंह, बागपत। हिंडन और कृष्णा नदी के संगम तट पर स्थित महाभारत कालीन ऐतिहासिक नगरी बरनावा में श्री महानंद संस्कृत विद्यालय लाक्षागृह प्राचीन गुरु-शिष्य परंपरा का एक जीवंत प्रतीक बना हुआ है। वर्ष 1977 में स्थापित और 1980 में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मान्यता प्राप्त इस संस्थान में देश के विभिन्न प्रांतों से आए 160 विद्यार्थी प्राचीन गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था के तहत वैदिक शिक्षा का अध्ययन कर रहे हैं।

गांव के दक्षिण में 21 एकड़ भूमि पर फैले लगभग 88 फीट ऊंचे टीले को ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लाक्षागृह के नाम से जाना जाता है। यह टीला इस संस्थान की पृष्ठभूमि को और भी गौरवशाली बनाता है, जहां आधुनिक युग में भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की मूल धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। इस टीले के नीचे एक सुरंग भी है। ऐसा माना जाता है कि लाक्षागृह में कौरवों ने एक षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाकर मारने का असफल प्रयास किया था। पांडवों ने इस टीले के नीचे स्थित इसी सुरंग का प्रयोग सुरक्षित बच निकलने के लिए किया था।

1960 में ब्रह्मर्षि कृष्णदत्त महाराज ने

लाक्षागृह पर आकर पर्यावरण की शुद्धि एवं मानव जीवन की आत्मिक उन्नति के लिए यज्ञशाला का निर्माण कर ईश्वरीय वेद वाणी द्वारा यज्ञ शुरू किया। इसके बाद यहां प्रतिवर्ष होली से पूर्व चतुर्वेद पारायण महायज्ञ का आयोजन शुरू किया। जिसका यहां निरंतर आयोजन हो रहा है। जिसमें देश-विदेश से श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। 1977 में महर्षि महानंद के नाम से संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। जिसके बाद यहां विभिन्न प्रदेशों के विद्यार्थी प्राचीन गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था में अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 1980 में इसे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से मान्यता मिली। फिर वर्ष 2000 में प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन किया गया।

गांधी धाम समिति द्वारा संचालित गुरुकुल में प्रदेश के विभिन्न जनपदों सहित हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश व नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्रांत के करीब 160 विद्यार्थी आवासीय व्यवस्था में रखकर अध्ययन कर रहे हैं। यहां अब कान्वेंट स्कूलों की तर्ज पर स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। इसमें विद्यार्थी देववाणी का पाठ करते हैं। खास बात यह है कि संस्कृत विद्यालय में प्रदेश के अलावा

सुभाष परासर/एजेंसी, कोलकाता। कोलकाता के सॉल्टलेक स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू किया गया है। यहां एक ही मरीज के इलाज में दो चिकित्सा पद्धतियों की भूमिका देखने को मिलेगी। आवश्यकता पड़ने पर मरीज का ऑपरेशन एलोपैथी चिकित्सक करेंगे, आपरेशन के बाद की देखभाल में होम्योपैथी दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। संस्थान का उद्देश्य इसके प्रभाव का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना है।

एनआइएच के निदेशक प्रलय शर्मा के अनुसार, संस्थान के ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। यदि किसी मरीज की बीमारी ऐसी है, जिसमें सर्जिकल प्रक्रिया जरूरी है, तो केवल होम्योपैथी दवा पर निर्भर रहने के बजाय आवश्यक ऑपरेशन कराया जाएगा। इसके बाद पोस्ट-ऑपरेटिव मैनेजमेंट में होम्योपैथिक दवाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। देखा जाएगा कि मरीज के दर्द, रिकवरी और घाव भरने की प्रक्रिया पर होम्योपैथी का क्या प्रभाव पड़ता है।

इन पहलुओं का क्लिनिकल रिसर्च के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। संस्थान के नियमित मरीज को आपरेशन की जरूरत पड़ने पर बाहर रेफर करने के बजाय एनआइएच में ही उसके उपचार की पूरी व्यवस्था करने की योजना है। ऑपरेशन के दौरान एनेस्थेसिस्ट, सर्जन और जरूरत के अनुसार कार्डियोलॉजिस्ट की भूमिका एलोपैथी चिकित्सक निभाएंगे।

राजस्थान, हरियाणा समेत अन्य राज्यों के देववाणी के उपासक विद्यार्थी कंप्यूटर में भी महारथ हासिल कर रहे हैं। गुरुकुल में शिक्षक दिवस पर अध्ययनरत विद्यार्थी गुरु वंदना कर आशीष प्राप्त करने के साथ ही गुरुजनों को अंगवस्त्र भेंट करते हैं।

सब जूनियर नेशनल फुटबाल चैंपियनशिप में कई भाषा और सभ्यता का संगम नजर आया
बागपत। गोपीचंद महाविद्यालय, अहैड़ा में चल रही बालक-बालिका वर्ग की नाइन साइड सब जूनियर नेशनल फुटबाल चैंपियनशिप में कई भाषा और सभ्यता का संगम नजर आया।

तेलंगाना के हैदराबाद का मुस्लिम परिवार तीन बेटियों के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुआ। परिवार का मानना है कि बेटियों पर हिजाब की बंधि नहीं, उनका करियर जरूरी है। बेटियां हमारा अभिमान हैं। बेटियों के कदमों को धर्म की बेड़ियां कभी नहीं जकड़ पाएंगी।

हैदराबाद निवासी फुटबाल कोच मोहम्मद असलम अपनी फुटबालर पत्नी फौजिया बेगम और तीन बेटियों जैनब अलीना, हाजिया सफा, इका फातिमा के साथ प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं।

नोट: पत्र में छपे लेख, लेखकों के निजी विचार हैं, सम्पादक का इनसे सहमत होना अनिवार्य नहीं है। आप स्वयं जांच करें। किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र बागपत होगा।

RNI. No. UPHIN/2010/36806, मालिक, मुद्रक, प्रकाशक सुभाष चन्द ने इण्डियन प्रेस, राजेन्द्र नगर, मेरठ से छपवाकर कार्यालय ग्राम वाजिदपुर, पोस्ट तहसील बडौत, जिला बागपत से प्रकाशित किया। सम्पादक: सुभाष चन्द, मो. 9837749557, प्रबन्धक सम्पादक: राजवीर सिंह, (किसी भी विवाद के लिए बागपत न्यायालय मान्य)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी में अत्याधुनिक ऑपरेशन

बच्चों में पनपने वाली नशे की आदत और बढ़ते स्क्रीन टाइम के प्रति आगाह

सपना कश्यप/एजेंसी, नई दिल्ली। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर चुने हुए शिक्षकों से मुलाकात में प्रधानमंत्री ने बच्चों में पनपने वाली नशे की आदत और बढ़ते स्क्रीन टाइम के प्रति आगाह किया। पीएम मोदी ने इस दौरान शिक्षकों को सलाह दी कि वह बच्चों को सिलेबस से बाहर निकल उसके व्यवहार और आदतों पर भी ध्यान दें। इस साल 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अपने आवास पर शुक्रवार शाम को हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों को बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन से परे जाकर उनके व्यवहार और दैनिक जीवन पर भी ध्यान देना चाहिए।

पारंपरिक संयुक्त परिवार व्यवस्था में कमी के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल होने वाली दवाओं में होम्योपैथी को शामिल किया जाएगा। एनआइएच में बैचलर आफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी पाठ्यक्रम संचालित होता है। पाठ्यक्रम के नाम में ही सर्जरी शामिल है। नए मॉड्यूलर आपरेशन थिएटर के जरिए छात्रों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि किन बीमारियों में ऑपरेशन जरूरी होता है और किन स्थितियों में दवाओं से उपचार संभव है।

बच्चों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रधानमंत्री ने नशे की समस्या के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों से बच्चों में होने वाले बदलावों के प्रति सतर्क रहने, इसके कारणों का पता लगाने और ऐसे बच्चों को इस लत से उबरने में मदद करने का विशेष प्रयास किया जाना चाहिए।

बचपन की मासूमियत को सुरक्षित रखना एक महत्वपूर्ण भूमिका है और शिक्षक यह भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों में एक समान मूल स्वभाव और जिज्ञासा होती है और यदि शिक्षक इस जिज्ञासा को बढ़ावा और उचित दिशा दें, तो वे उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। स्क्रीन टाइम आज हर किसी के लिए बड़ी समस्या है। बच्चों में इसकी लत ज्यादा चिंताजनक है।

केशरी दर्पण समाचार पत्र के ऑनलाइन पत्रकार बने।

www.kesharidarpan.com

पर रजिस्टर/लॉगिन करें।



सम्पादक सुभाष चंद
9837749557

उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में जनसंख्या गणना एक दिसंबर से चार जनवरी तक

गृह मंत्रालय ने सात जनवरी 2026 को जारी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू करने की बात कही गई थी।

तरुण/एजेंसी, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के कुछ हिस्सों में जनसंख्या गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी। अगले साल की शुरुआत में चुनाव संभावना वाले इन राज्यों में यह प्रक्रिया समय से पहले पूरी की जा रही है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि इन क्षेत्रों के नागरिक 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का विकल्प चुन सकते हैं।

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में जनसंख्या जनगणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक

की जाएगी। पांच जनवरी से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण चरण आयोजित किया जाएगा। पिछले महीने जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना एक से 30 सितंबर तक होगी। इन क्षेत्रों के लिए स्व-गणना की अवधि 17 से 31 अगस्त तक खुली थी।

पिछले साल जून में, सरकार ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, देश के लिए जनगणना संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 रात 12 बजे घोषित की थी। वहीं एजेंसी के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने शनिवार को मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए घरों की सूची बनाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। यह कार्य अगली घोषणा तक के लिए स्थगित रहेगा।

गृह मंत्रालय ने सात जनवरी 2026 को जारी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू करने की बात कही गई थी।